

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेंद्र गोयल

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 84

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिये सरकार द्वारा कितना फंड आवंटित किया गया है;	डी.एस.आई.आई.डी.सी वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। अनाधिकृत कॉलोनी सेल, शहरी विकास वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार ने 2018-19 में 795 करोड़ का बजट रखा है जिसे 250/- करोड़ की धन राशि शहरी विकास विभाग सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को दे चुका व 100/- करोड़ डीएसआईआईडीसी को देने के लिए फाईल प्रस्तुत है।
ख	इस आवंटित फंड का कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ.	डी.एस.आई.आई.डी.सी वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। अनाधिकृत कॉलोनी सेल, शहरी विकास शहरी विकास विभाग द्वारा एक मुश्त धन राशि डी.एस.आई.आई.डी.सी, दिल्ली जल बोर्ड, सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण एवं पॉवर आदि विभागों को जारी की जाती है, तदुपरान्त निष्पादन एंजिनियर्स द्वारा उक्त जारी एक मुश्त राशि से अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य करवाया जाता है। शहरी विकास विभाग द्वारा क्षेत्रानुसार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।
ग	क्या यह सत्य है कि डीएसआईआईडीसी को आवंटित फंड पूरा खर्च नहीं हो पाया; और	डी.एस.आई.आई.डी.सी वर्तमान वित्त वर्ष में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है।
घ	क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास बोर्ड का आवंटित फंड भी पूरा खर्च नहीं हो पाया?	कार्यालय सचिव-सह विकास आयुक्त दिल्ली सरकार का विकास विभाग (दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड) इसकी कार्य प्रणाली व प्रशासनिक देखभाल करता है। उप-सचिव, विकास, विभाग, प्लन क्रमांक 2148 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा आवंटित फंड का विस्तृत ब्यौरा तथा उसके खर्च का हिसाब-किताब पत्राकांक पर संलग्न है।

**NUMBER OF PROJECT PROPOSALS APPROVED BY THE DVDB (MEETING WISE) WITH AMOUNT
IN THE CURRENT FINACIAL YEAR 2018-19 (AGAINST THE APPROVED OULTLAY OF RS. 200 CR)**

S.No	Date of Meeting	Numbers of approved project proposals	Amount(in Crore)
1	21/12/2017	104	120.26
2	19/01/2018	349	434.17
3	12.02.2018	380	309.62
4	13.04.2018	132	126.71
5	23.05.2018	104	143.59
	Total	1069	1134.45

DETAILS OF SANCTIONS ISSUED BY THE RD UNIT IN RESPECT OF DVDB APPROVED WORKS IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2018-19 (AS ON 9.8.2018)

Sr. No.	Name of PC/AC	Name of MLAs	No. of Projects Sanctioned	Amount of Sanctions issued Till the 1st qtr. (Rs. in Crore)
1	Badli	Sh. Ajesh Yadav	1	3.3
2	Bawana	Sh. Ramchander	5	3.68
3	Bijwasan	Col.Devender Sehwat	1	0.87
4	Burari	Sh. Sanjeev jha	13	13.94
5	Kirari	Sh. Rituraj Govind	1	0.65
6	Mangol puri	Ms. Rakhi Birla	1	2.71
7	Matiala	Sh.Gulab Singh	13	6.32
8	Mundka	Sh. Sukhbir Singh Dalal	8	9.34
9	Najafgarh	Sh. Kailash Gahlot	12	21.90
10	Narela	Sh. Sharad Kumar Chauhan	12	12.42
11.	Rithala	Sh. Mohinder Goyal	1	0.92
		Total	68	76.05*

***Note:-** Against the above sanctioned amount, I&FC Deptt- the main Executing Engineering Agency, has reportedly spent Rs. 30 Crores (approx) up to 31.07.2018.

**MANDATED DEVELOPMENT WORKS BEING UNDERTAKEN BY THE DVDB AND DETAIL OF EXECUTING
ENGINEERING AGENCIES (EEA)**

1. THE FOLLOWING NATURE OF WORK CAN BE RECOMMENDED BY THE DVDB IN THE RURAL AND URBAN VILLAGES OF NCT OF DELHI IN LAL DORA AREAS, SIZRA ROADS AND PUBLIC UTILITIES ON GOVT. LAND EXCEPT IN UNAUTHORIZED COLONIES OF ANY STATUS AND RESETTLEMENT COLONIES AND JJ BASTIS FALLING UNDER THE JURISDICTION OF DUSIB:
 - (i) CONSTRUCTION OF APPROACH ROADS/LINK ROADS/VILLAGE ROADS.
 - (ii) DEVELOPMENT OF PONDS/WATER BODIES.
 - (iii) DEVELOPMENT OF CREMATION GROUNDS, PARKS, PLAYGROUNDS, VYAYAMSHALAS, VILLAGE LIBRARIES.
 - (iv) CONSTRUCTION OF DRAINAGE FACILITIES.
 - (v) CONSTRUCTION/REPAIR/MAINTENANCE OF CHAUPALS, BARAT GHARS, COMMUNITY CENTRES.
 - (vi) OTHER NEED BASED WORKS, LIKE DRINKING WATER FACILITY, STREET LIGHTS ETC.

2. **EXECUTING ENGINEERING AGENCIES:-** THE ABOVE MENTIONED CAPITAL WORKS RECOMMENDED DVDB ARE EXECUTED THROUGH VARIOUS GOVT. AGENCIES LIKE I&FC, SDMC, NDMC, DJB ETC.